



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2003/श्रावण 9, 1925

No. 186]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2003/SRAVANA 9, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2003

विषय :—चीन और जापान के मूल अथवा वहां से आयातित विटामिन-सी के आयातों से सम्बन्धित पाटनरोधी जांच (निर्णायक समीक्षा)—अंतिम जांच परिणाम।

सं. 14/14/2002-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

तथा इसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क प्रक्रिया

1. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है: -

अधिसूचना संख्या 11/1/97-एडीडी दिनांक 25.05.1998 द्वारा अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था जिसमें चीन जन. गण. एवं जापान के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन सी के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, शुल्क को सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 53/987 दिनांक 24.07.1998 के द्वारा लगाया गया था।

- (ii) सीमा टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगातार जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करनी अपेक्षित होती है। भारतीय उत्पादकों में से किसी एक उत्पादक द्वारा दायर की गई याचिका के परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 11/1/99 दिनांक 9.7.1999 के द्वारा चीन जन. गण. तथा जापान के मूल के या वहां के निर्यातित विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करने हेतु एक सार्वजनिक सूचना जारी की तथा पाटनरोधी शुल्क जारी रखना उचित माना जिसे दिनांक 13.6.2000 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- (iii) घरेलू उद्योग मैसर्स साराभाई एम. कैमिकल्स ने अब चीन जन. गण. और जापान के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।
- (iv) मौजूदा लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 2936.27 के तहत वर्गीकृत संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा आरंभ करते हुए दिनांक 14 अगस्त 2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था।
- (v) प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना, घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई अगोपनीय याचिका तथा प्रशानवली प्रोफार्मा की एक-एक प्रति भेजी ताकि वे संगत सूचना दे सकें तथा प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर सकें:

- i) मैसर्स टाकेडा कैमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जापान (मैसर्स बी ए एस एफ) ।
 - ii) मैसर्स नेशनल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन, चीन ।
 - iii) मैसर्स हिब्यू व्हेलकम, चीन ।
- (vi) प्राधिकारी ने ज्ञात आयातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के उपयोगकर्ताओं को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना, घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई अगोपनीय याचिका तथा प्रश्नावली प्रोफार्मा की एक-एक प्रति भेजी ताकि वे संगत सूचना दे सकें तथा प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर सकें:

- i) मैसर्स सॉफ्टसूल प्रा. लि., मुंबई
- ii) मैसर्स फार्मापाक प्रा. लि., मुंबई
- iii) मैसर्स ईएसपीआई इंड एंड कैमि. प्रा. लि., हैदराबाद
- iv) मैसर्स ओमनी प्रोटेक ड्रग्स लि. पुणे
- v) मैसर्स ई मर्क इंडिया लि., रायगढ़
- vi) मैसर्स वाइथ लैडरल लि., गुजरात
- vii) मैसर्स साईक्योर फार्मा प्रा.लि. अहमदाबाद
- viii) मैसर्स एंगलो फैच ड्रग्स एंड इंड लि., बंगलोर
- ix) मैसर्स वाइटल थिरैपिक्यूटिज प्रा. लि., सिकंदराबाद
- x) मैसर्स आवित्र कैमिकल्स प्रा. लि., औरंगाबाद
- xi) मैसर्स अम्सट्रिन फार्मा प्रा. लि., मुंबई
- xii) मैसर्स स्विफ्ट कैमि. लि, मुंबई
- xiii) मैसर्स स्ट्राईड फार्मा लि. मुंबई
- xiv) मैसर्स साई मीरा इन्फोफार्मा, चैन्नई
- xv) मैसर्स सेन मेडिकेमिन्ट्स प्रा. लि. हैदराबाद

- xvi) मैसर्स गांधी फार्मा, चैन्नई
 - xvii) मैसर्स ग्लैक्सो स्मिथलाइन फार्मा, मुंबई
 - xviii) मैसर्स हेंज इंडिया लि., अलीगढ़
 - xix) मैसर्स मेयर आर्गेनिक्स लि., थाणे
 - xx) मैसर्स टोरेट फार्मा लि, मेहसाना
 - xxi) मैसर्स सुमे फार्मा प्रा. लि., भीमावरम
 - xxii) मैसर्स टीके मैथोल प्रा.लि., मुंबई
 - xxiii) मैसर्स सेफैक्स इंट. अहमदाबाद
 - xxiv) मैसर्स विंकीज इंडिया लि.
 - xxv) मैसर्स कारे लैब्स प्रा. लि.
 - xxvi) मैसर्स रेमीडैक्स फार्मा प्रा. लि., बंगलौर
 - xxvii) मैसर्स लिवा फार्मा लि., नासिक
 - xxviii) मैसर्स माइक्रो नोवा फार्मा , बंगलोर
 - xxix) मैसर्स बजाज हेल्थकेयर प्रा. लि., मुंबई
 - xxx) मैसर्स कैम इनोवा रेमीडीस, हैदराबाद
 - xxxi) मैसर्स ईमिल फार्मा इंड, थाणे
 - xxxii) मैसर्स डा. रेड्डीज लैब, आंध्र प्रदेश
 - xxxiii) मैसर्स फाईजर लि, मुंबई
 - xxxiv) मैसर्स सीएफएल फार्मा लि., गोवा
 - xxxv) मैसर्स बिसिक्का फार्मा एंड कैमि., मुंबई
 - xxxvi) मैसर्स बैजल फार्माकैप. बालसार
 - xxxvii) मैसर्स बीएएसएफ इंडिया लि. नवी मुंबई
- (vii) प्राधिकारी ने भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना, घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई अगोपनीय याचिका तथा प्रश्नावली प्रोफार्मा की एक-एक प्रति भेजी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे

अपने अपने देश के उत्पादकों तथा निर्यातकों को निर्धारित प्रोफार्मा में निर्धारित समयावधि के भीतर जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का जवाब देने के लिए कहे ।

- (viii) संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत सूचना नहीं भेजी ।
- (ix) प्राधिकारी ने दिनांक 15 जनवरी, 2003 को सभी संबद्ध पार्टियों को मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें । पार्टियों को विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों तथा उसके खंडन, यदि कोई हो, की प्रतियां एकत्र करने की सलाह दी गई ।
- (x) हितबद्ध पार्टियों द्वारा अनुरोधों के लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है ।
- (xi) पूर्वोक्त नियम 16 के अनुसार, ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को इस जांच परिणामों के लिए आवश्यक तथ्य/आधार की जानकारी दी गई थी तथा इनपर प्राप्त विचारों पर इन परिणामों में विधिवत रूप से विचार किया गया है ।
- (xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंशों को सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

- (xiii) प्राधिकारी ने सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर भारत में विटामिन-सी के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा इसके बनाने तथा बेचने की लागत निकालने के लिए भी लागत जांच की ।
- (xiv) यह जांच 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 (12 माह) तक की अवधि के लिए की गई थी ।
- (xv) *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माने जाने का द्योतक है ।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

2. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रमुख अनुरोध किए हैं: -

2.1 वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद अपने सभी रूप तथा व्युत्पत्तियों में विटामिन-सी है । इसे एसकार्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है । यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष संख्या 2936.27 के तहत वर्गीकृत है । यह विभिन्न पर्यायवाची यथा - एल - जायलोएसकार्बिक एसिड, 3 - आक्सो एल - ग्लूलोफ्यूरानो लैक्टोन (एनॉल फार्म), एल - 3 किटाथ्रिपोहेक्सयूरोनिक एसिड लैक्टोन इत्यादि, जैसा कि "मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या 867" के तहत उल्लिखित है, के नाम से भी जाना जाता है ।

2.2 चीन के निर्यातकों ने भारत में माल का पाटन जारी रखा । वस्तुतः चीन के निर्यातकों ने भारत में अपने निर्यात के संबंध में कीमतों में आगे और कमी की । इस प्रकार चीन से पाटन में बढ़ोतरी हुई है ।

2.3 जिस कीमत पर माल का निर्यात किया जा रहा था, वह न केवल पाटित मूल्य था, बल्कि उससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति भी हुई थी। चीन से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को लगातार वास्तविक क्षति होती रही। इसके अलावा, लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहेगी/पुनारावृत्ति होती रहेगी।

2.4 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों पर इन जांच परिणामों में संबंधित स्थानों पर विचार किया गया है।

2.5 बी ए एस एफ द्वारा व्यक्त विचारों पर याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रमुख निवेदन किए हैं: -

क. बी ए एस एफ भारत अथवा बी ए एस ए जर्मनी ने किसी भी प्रश्नावली का जवाब नहीं भेजा है। अतः बी ए एस एफ की वर्तमान भागीदारी संगत जानकारी उपलब्ध कराए बिना है। याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह बी ए एस एफ को असहयोगी पार्टी घोषित करे।

ख. निर्यातक ने शुल्क वापस लेने के औचित्य संबंधी कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है। केवल इस तर्क से कि जांच अवधि के बाद उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हुई, जांच समाप्त नहीं की जा सकती है अथवा शुल्क वापस नहीं लिया जा सकता है। जांच अवधि के बाद के आंकड़ों/सूचनाओं की पाटनरोधी जांच में कोई प्रासंगिकता नहीं है। याचिकाकर्ता मानता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसा ही किया जाता है। किसी भी मामले में अलग से कोई भी मापदंड देखा नहीं जा सकता। बी ए एस एफ ने इस बात से भी इंकार नहीं किया है कि जांच अवधि के बाद सामान्य मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है।

ग. याचिकाकर्ता पहले बुनियादी चरण से विटामिन सी का उत्पादन कर रहा था । तथापि विभिन्न स्रोतों से लगातार जारी पाटन ने घरेलू उद्योग को मध्यवर्ती अर्थात् 2 के जी ए से उत्पादन (जो कि सस्ता है) करने के लिए बाध्य किया । चूंकि कंपनी बुनियादी चरण से उत्पादन के लिए सक्षम है, अतः 2 के जी ए की अनुपलब्धता से याचिकाकर्ता को कोई अड़चन नहीं आएगी । बी ए एस एफ का संपूर्ण तर्क दोषपूर्ण तथा असंगत है ।

घ. यह समझ से परे है कि यदि पाटनरोधी शुल्क जारी रहा तो विटामिन सी की बढ़ती आयात कीमतें किस प्रकार उन प्रतिपादकों को लाभ पहुंचाएगी जो डी पी सी ओ के अंतर्गत हैं । उत्पाद यथामूल्य नहीं है अथवा इसमें पाटनरोधी शुल्क की निश्चित राशि शामिल नहीं है । उत्पाद में शुल्क परिवर्ती रूप में है तथा यदि निर्यात कीमतें बढ़ती हैं तो शुल्क कम हो जाएगी ।

ङ. यह देखा जाएगा कि बी ए एस ए द्वारा दिए गए तर्कों में कोई गुण नहीं है । बी ए एस एफ ने यह विवाद नहीं उठाया है कि उत्पाद का पाटन जारी है तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी है । और न ही बी ए एस एफ ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क वापस लेने से फिर से पाटन तथा क्षति नहीं होगी । ऐसी स्थिति में जापान तथा चीन से विटामिन सी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की पुष्टि के पर्याप्त आधार हैं ।

ग. निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार:

निर्यातक

3.1 बी ए एस एफ एजी का अभ्यावेदन

- (क) बी ए एस एफ एजी ने कहा है कि उसे घरेलू उद्योग द्वारा दायर समीक्षा याचिका की अगोपनीय अंश उपलब्ध नहीं कराया गया था । स्थानीय उत्पादक साराभाई कैमिकल्स ने यह समीक्षा याचिका दायर की है तथा प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वर्तमान प्राटनरोधी शुल्क बढ़ाने पर विचार किया जाए ।
- (ख) बी ए एस एफ एजी ने कहा है कि उसने जांच अवधि के दौरान जापान के मूल के किसी भी विटामिन सी का निर्यात नहीं किया है ।
- (ग) बी ए एस एफ का विचार है कि विगत 5 वर्षों से स्थानीय उत्पादक को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए काफी समय तथा अवसर दिया गया है तथा यदि इस अवधि के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है तो तार्किक रूप से इस अवधि को पुनः बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

आयातक

3.2 मैसर्स बजाज हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

जांच शुरुआत के जवाब में, अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने याचिका की अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था । अनुरोध के अनुसार, हमारे पत्र संख्या 14/14/2002-डीजीएचडी दिनांक 6.1.2003 द्वारा कंपनी को अगोपनीय अंश की एक प्रति भेज दी गई थी । प्रकटन के जवाब में, इन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें विभिन्न मामलों के मुख्य बातों को रखा है जिस पर इस जांच परिणाम के संगत पैराग्राफ में विचार किया गया है । कंपनी द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं : -

- i) घरेलू उद्योग की याचिका की अगोपनीय अंश में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है ।
- ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उपबंधों के विपरीत है । जांच शुरुआत की नोटिस दिनांक 14.8.2002 के अनुसार नियम 6(1) के अनुसार पर्याप्त जानकारी निहित नहीं है ।
- iii) जांच सिर्फ संबद्ध देशों से भारत में आयातित बी पी/यूएसपी विशिष्ट वाले विटामिन सी तक ही सीमित रखी जाए ।
- iv) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में नहीं है ।
- v) याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में जानकारी गोपनीय रखी है ।
- vi) याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन प्रोफार्मा आई वी ए तथा आई वी बी के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है ।
- vii) नियमावली 12(1) के उपबंधों के अनुसार, प्राधिकारी उपर्युक्त पाटनरोधी जांच में पाटन क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संदर्भ में प्रारंभिक जांच परिणाम निकालने के लिए बाध्य हैं ।
- viii) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी आई है, तथापि प्राधिकारी का यह कथन है कि याचिकाकर्ताओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है ।

- ix) नियम का उल्लंघन करते हुए प्राधिकारी ने मनमाने ढंग से चीन तथा जापान में विटामिन सी की सभी प्रक्रियाओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया है । (नियम 17(3))

3.3 मैसर्स लिवा हैल्थ केयर लिमिटेड, मुंबई

इन्होंने कहा है कि विटामिन सी की इनकी खपत नगण्य है तथा वे सार्वजनिक सुनवाई/जांच में भाग नहीं लेंगे ।

(घ) प्राधिकारी द्वारा जांच तथा जांच परिणाम

- 4.0 आयातकों, निर्यातकों, उपयोगकर्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की जांच की गई है तथा इस परिणाम पर पहुंचने के लिए इस पर विचार किया गया है तथा जहां कहीं उचित समझा गया है उन पर आगे कार्रवाई की गई है ।

पूर्वोक्त नियमावली के अनुसार अनुरोध करने पर, प्राधिकारी द्वारा नए निर्यातक अथवा कीमत-वचन देने के इच्छुक निर्यातकों के मामलों पर विचार किया जाएगा ।

ड. विचाराधीन उत्पाद

- 5.0 वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन तथा जापान के मूल के या वहां से निर्यातित विटामिन सी और सामान्यता प्रयोग होने वाले विटामिन सी और सामान्यतः प्रयोग होने वाले विटामिन सी के पर्यायों जैसे एसकार्बिक एसिड, एल साइलोएसकार्बिक एसिड 3 आक्सो एल गुलो फरानों लैक्टोन (इनोल रूप) एल 3 केटोथिओ हैक्सोरोनिक एसिड

लैक्टोन आदि जिसका विवरण मर्क इन्डैक्स की प्रविष्टि संख्या 867 में दिया गया (जिन्हे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) है । विटामिन सी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के उपशीर्ष संख्या 2936.27 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

5.1 बजाज हैल्थकेयर द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों में घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया तथा उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया में अंतर है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो संबद्ध देशों के उत्पादकों ने समीक्षा जांच का जवाब दिया और न ही उत्पादन प्रक्रिया में अंतर होने का दावा किया, और न ही मैसर्स बजाज हैल्थकेयर ने आरोपित अंतर हेतु कोई दस्तावेजी सबूत ही प्रस्तुत किया है । ऐसी परिस्थिति में, विनिर्माण प्रक्रिया में आरोपित अंतर के संबंध में दिए गए तर्क अस्वीकार किए जाते हैं ।

5.2 उत्पादन प्रक्रिया में अंतर होने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को फार्मा ग्रेड तक सीमित करने को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई अकाट्य तर्क नहीं दिया गया है । यह सिद्ध नहीं किया गया है कि यह भारत को आयातित विटामिन सी का एकमात्र रूप है । आगे, यह साबित नहीं किया गया है कि फार्मा ग्रेड विटामिन सी तथा अन्य प्रकार अलग उत्पाद हैं तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक मैसर्स बजाज हैल्थकेयर ने आयातक की प्रश्नावली के अनुसार जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है । अतः प्राधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद में विटामिन सी के सभी रूप शामिल हैं ।

5.3 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन तथा जापान के मूल के तथा वहां से निर्यातित विटामिन सी

है । विटामिन सी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत उपशीर्ष 2936.27 के तहत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण सांकेतिक है तथा किसी भी तरह वर्तमान याचिका के कार्यक्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है ।

च. समान वस्तु

6.0 पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तु वह वस्तु है जो हर दृष्टि से जांचाधीन उत्पाद के समरूप एवं समान हो तथा ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में ऐसी दूसरी वस्तु है जो जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से बहुत मिलती जुलती हो ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बेचे जाने वाले तथा संबद्ध देशों से आयातित विटामिन सी में कई समानताएं हैं इसलिए उन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए । याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा चीन से आयात किया जाने वाला विटामिन सी, भौतिक तथा रासायनिक गुणों, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विशिष्टियां, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण आदि विशेषताओं के आधार पर तुलनीय है । हालांकि एक आयातक का तर्क कि दोनों की उत्पादन प्रक्रिया भिन्न है, निराधार तथा असंपुष्ट है, और यदि यह मान भी लिया जाए कि उत्पादन प्रक्रिया में भिन्नता है तो भी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा चीन से आयातित विटामिन सी, तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है । उपयोक्ता दोनों को अदल बदल कर प्रयोग में ला रहे हैं ।

7.0 प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि इस बात का खंडन करते हुए कोई तर्क नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विटामिन सी में आयातित सामग्री से काफी मिलती जुलती विशेषताएं हैं और यह वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों रूपों में संबद्ध देशों से आयातित विटामिन सी द्वारा प्रतिस्थापनीय है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विटामिन

सी को नियम 2(घ) के अर्थों के भीतर चीन से निर्यातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है ।

छ. घरेलू उद्योग

8.1 वर्तमान जांच इस तथ्य के परीक्षण के लिए निर्णायक समीक्षा जांच है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होगी अथवा निरंतरता बनी रहेगी । आगे मै. अंबालाल साराभाई इंटरप्राइजेज़ लि. द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिनका पंजीकृत कार्यालय वाडी, बड़ौदा - 390007 में है । भारत में विटामिन सी के कई अन्य उत्पादक भी हैं । मै. अमोली आर्गेनिक्स लि. भी इस उत्पाद का उत्पादक है, जिन्होंने इस याचिका का समर्थन किया है । पूर्व में मै. जयंत विटामिन लि. ने विटामिन सी के उत्पादन में अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी । तथापि, कंपनी ने लंबे समय से उत्पादन को बंद कर दिया है । नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (एन पी पी ए) द्वारा प्रदत्त सूचना से इस तथ्य की पुष्टि होती है ।

8.2 प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. न्यू एस- हेम सर्च लि. वड़ोदरा और मै. कर्ब्स बायोकेमिकल्स लि. हैदराबाद ने जांच अवधि के पश्चात उत्पादन प्रारंभ कर दिया है; जबकि अन्य एकक जैसे मै. कार्डिनल ड्रग्स लि. मै. टोनिरा फार्मा इत्यादि कथित रूप से निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन कर रहे हैं । हालांकि मै. बजाज हेल्थ केयर ने घरेलू उद्योग के रूप में अंबालाल साराभाई के तर्कों का प्रतिवाद किया है, फिर भी कंपनी ने संबद्ध उत्पादों के संबंध में इन कंपनियों में से किसी एक की अथवा स्वयं की स्थिति के बारे में कोई परिमाणक आंकड़े नहीं दर्शाए हैं ।

8.3 प्राधिकारी अंबालाल साराभाई ने घरेलू उद्योग की स्थिति एवं कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराई है । आधार संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में यह दोहराया गया है कि वर्तमान जांच समीक्षा जांच है जो धारा 9क(5) तथा नियम 23 के

अनुसार शुरू की गई है और इसलिए नियम 5 के तहत आने वाली अपेक्षाएं यहां आवश्यक नहीं हैं।

- 8.4 स्पष्ट किया गया है कि अमोली आर्गेनिक्स ने याचिका का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, केवल अंबालाल साराभाई द्वारा किया जा रहा उत्पादन ही भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है।
- 8.5 उपरोक्त को देखते हुए तथा विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि भारतीय उत्पादन में अंबालाल साराभाई का एक प्रमुख हिस्सा है और इसलिए वे पाटनरोधी नियमों के तहत घरेलू उद्योग है।

9-0 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन

9-1 धारा 9 क (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है: -

- (i) "सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा(6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या
- (ii) जहां निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो अथवा विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो: -

(क) निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत तहत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत ।

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुज़री हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो अथवा निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।"

9.2 मै. बी ए एस एफ एक्टिंग सेल शाफ्ट, लुडविगशाफान, जर्मनी द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन: -

निर्णायक समीक्षा जांचों के प्रारंभ किए जाने के उत्तर में दिनांक 19 सितंबर 2002 को अपने फैक्स में उन्होंने कहा है कि

(क) वे विश्व भर में विटामिन सी के प्रमुख उत्पादकों एवं पूर्तिकर्ताओं में से एक हैं तथा जांच का उत्तर देना चाहते हैं ।

(ख) मै. बी ए एस एफ एवं तकेदा ने अपने जल में घुलनशील विटामिन के व्यापारों को 4 जनवरी 2001 से आमेलित कर दिया है । करार की शर्तों के तहत

तकेदा जापान, हिकरी जापान में अपने विनिर्माण स्थल पर विटामिन सी सहित जल में घुलनशील विटामिनों का उत्पादन करना जारी रखेगा ।

- (ग) मै. तकेदा जापान, उत्पादों का व्यापार नहीं करता है क्योंकि यह बी ए एस एफ और उसकी ग्रुप कंपनियों का दायित्व है ।
- (घ) बी ए एस एफ ने जांच की अवधि के दौरान भारत को तकेदा जापान द्वारा विनिर्मित जापानी मूल के किसी भी विटामिन सी का निर्यात नहीं किया ।
- (ङ) बी ए एस एफ ने जांच की अवधि के दौरान भारत को चीन मूल के किसी भी विटामिन सी का निर्यात नहीं किया ।
- (च) जहां तक भविष्य में भारत को निर्यातों का संबंध है, वे नई शिपर समीक्षा का अनुरोध करेंगे ।

9.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- (क) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में विटामिन सी के सभी ज्ञात निर्यातकों तथा उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी । तथापि, संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप एवं तरीके में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की । अतः प्राधिकारी का सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना अर्थात् परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर कार्रवाई करना पूरी तरह से विधि सम्मत है ।
- (ख) याचिकाकर्ता ने डी जी सी आई एंड एस कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है । निर्यात कीमत में कमीशन,

अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमे, पैकिंग एवं हैंडलिंग प्रभारों के लिए समायोजन किया गया है ।

9-4 प्राधिकारी की स्थिति - सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण

प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में विटामिन सी के सभी ज्ञात निर्यातकों तथा उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी । तथापि, संबद्ध देशों से किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप एवं तरीके में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की । प्राधिकारी के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ।

याचिकाकर्ता ने उत्पादन लागत के आकलनों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं सूचना की सावधानीपूर्वक जांच की है और उचित समायोजन किए हैं । इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है ।

याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है । चीन से किसी निर्यातक से सहयोग की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के अनुसार सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है ।

डी जी सी आई एंड एस कीमते सी आई एफ कीमतें हैं । व्यापार के समान स्तर पर तुलना के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा प्राधिकारी

के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमे, पैकिंग एवं हैंडलिंग प्रभारों के लिए निर्यात कीमत का समायोजन किया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से आयातों की मात्रा एवं सी आई एफ कीमत 800.17 रूपए/किग्रा की दर से 1699 किग्रा है। मात्राएं न्यूनतम से कम हैं और कोई पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।

9-5 पाटन मार्जिन

पाटन मार्जिन के निर्धारण से संबंधित नियमावली सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना निम्नानुसार उपलब्ध कराती है: -

"6(1) डम्पिंग मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत एवं सामान्य मूल्य में एक निष्पक्ष तुलना करेगा। यह तुलना समान स्तर के व्यापार पर की जाएगी, सामान्यतः यह कारखाना द्वार के स्तर पर एवं यथासंभव उसी अवधि में की गई बिक्री के स्तर पर होगी। कीमत की तुलनीयता को प्रभावित करने वाले अंतर के लिए प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर उचित रियायत दी जाएगी जिसमें बिक्री की शर्तों, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्रा, भौतिक विशेषताओं में अंतर तथा अन्य ऐसे अंतर भी शामिल हैं जिससे कीमत की तुलनीयता प्रभावित होती प्रतीत होती हो।"

9-6 सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत में एक निष्पक्ष तुलना के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध सूचना पर विचार किया है। यह तुलना कारखाना द्वार के स्तर पर की गई है, चूंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों ही कारखाना द्वार के स्तर पर है। यह तुलना निम्नलिखित पाटन मार्जिनों को दर्शाती है: -

देश	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	निर्यात कीमत के % के रूप में पाटन मार्जिन
चीन	xxx	xxx	xxx	208.13
जापान	---	---	---	न्यूनतम से कम

प्राधिकारी मानते हैं कि जापान से आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन भी न्यूनतम से कम हैं ।

झ. क्षति:

10.0 उपरोक्त नियम 11, अनुबंध II के अंतर्गत जब क्षति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका प्रभाव, ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामकारी प्रभावों समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए" घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा । मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गयी होती ।

10.1 बी ए एस एफ एजी द्वारा किए गए अनुरोध

क) यहां कम से कम तीन अन्य भारतीय उत्पादक हैं और वे भी मध्यवर्ती उत्पाद 2 केटो ग्युलोनिक (2 केजीए) की अनुपलब्धता से प्रभावित होंगे, जिसका उन सभी के द्वारा चीन से आयात किया जाता है । बी.ए.एस.एफ. समझता है कि इस समय चीन से इस मध्यवर्ती उत्पाद के लिए कोई प्रस्ताव अथवा पोत-

लदान नहीं है और यह स्थिति बनी रहेगी । कीमतों के वर्तमान रुझान के बने रहने की स्थिति में बी ए एस एफ को आशंका है कि चीन से 2 केजीए उपलब्ध नहीं होगा चूंकि चीनी उत्पादक तैयार उत्पादों के लिए बेहतर अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करना चाहेंगे ।

- ख) मध्यवर्ती उत्पादों की कीमत में अचानक एवं प्रबल परिवर्तन ने उन सभी निरूपणों की लाभप्रदता को पहले ही समाप्त कर दिया होता जो औषधि कीमत नियंत्रण आदेशों के अधीन है ।
- ग) वर्तमान विश्व बाजार कीमतें, मांग एवं आपूर्ति स्थिति जांच अवधि की तुलना में बिल्कुल भिन्न है । अतः किसी क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है और पाटन रोधी शुल्क को आगे बढ़ाए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

10.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध: - घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई क्षति के निर्धारण से संगत सभी सूचना प्रस्तुत की है । आगे, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मुख्य अनुरोध निम्नानुसार हैं: -

- क) बी ए एस एफ ने शुल्क को हटाए जाने को उचित ठहराने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है । मात्र इस तर्क से कि जांच अवधि के बाद उत्पाद की कीमत में वृद्धि हुई है, जांच की समाप्ति अथवा शुल्क की समाप्ति नहीं की जा सकती । जांच अवधि पश्चात् के आंकड़ों अथवा सूचना की पाटनरोधी जांच से कोई संगति नहीं है । याचिकाकर्ता समझते हैं कि यह निर्दिष्ट प्राधिकारी का व्यावहारिक अनुभव है । किसी भी मामले में किसी एक मापदंड को अलग से नहीं देखा जा सकता । बी ए एस एफ द्वारा यह भी खंडन किया गया कि जांच अवधि पश्चात् सामान्य मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है ।

- ख) बी ए एस एफ द्वारा यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण दिया गया है और अतः पाटनरोधी शुल्क को रद्द कर देना चाहिए । याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि बी ए एस एफ निर्णायक प्राधिकारी नहीं है ।
- ग) यदि पाटन और क्षति दोनों को समाप्त कर दिया जाए तो शुल्क को समाप्त किया जा सकता है । बी ए एस एफ के मामले में भी ऐसा नहीं है कि पाटन संबद्ध देशों से रोक दिया गया हो ।
- घ) इस मामले में निर्यातकों ने वस्तुतः कीमतों में कमी की है और कुछ हद तक पाटनरोधी शुल्क को समाविष्ट किया है । इस प्रकार संबद्ध देशों से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति होती रही है ।
- ङ) याचिकाकर्ता इससे पूर्व आधारभूत स्तर से विटामिन सी का उत्पादन कर रहा था । तथापि, अनेक स्रोतों से पाटन जारी रहने के कारण घरेलू उद्योग मध्यवर्ती अर्थात् 2 केजीए (जो कि सस्ता है) का उत्पादन करने के लिए बाध्य हुआ है । चूंकि कंपनी आधारभूत स्तर से उत्पादन करने के लिए सक्षम है इसिलिए 2 केजीए की अनुपलब्धता से याचिकाकर्ता को कोई अड़चन नहीं होगी । इस मुद्दे पर बी ए एस एफ का समूचा तर्क गुण दोष रहित और असंगत है ।
- च) यह समझ में नहीं आता है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने की स्थिति में विटामिन सी की आयात कीमतों में वृद्धि से उन विनिर्माताओं को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा जो डीपीसीओ के अधीन हैं । इस उत्पाद पर मूल्यानुसार अथवा निर्धारित पाटन रोधी शुल्क नहीं लगाया जा रहा है । उत्पाद पर शुल्क अलग-

अलग दर से लगाया जा रहा है और निर्यात कीमत में वृद्धि होने की स्थिति में इसमें गिरावट आएगी ।

- छ) यह देखा जा सकता है कि बी ए एस एफ द्वारा दिए गए तर्कों में कोई दम नहीं है । बी ए एस एफ ने घरेलू उद्योग के इस तर्क का खण्डन नहीं किया है कि उत्पाद का पाटन जारी है और घरेलू उद्योग को क्षति भी जारी है । बी ए एस एफ ने ही यह तर्क दिया है कि पाटन रोधी शुल्क लगाने से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति नहीं होगी । ऐसा मामला होने के कारण संबद्ध देशों से विटामिन सी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए रखने की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त आधार है ।
- ज) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी-के लिए यह मूल्यांकन करना अपेक्षित है कि ऐसे शुल्क के समाप्त करने से क्या क्षति होती रहने अथवा दोबारा होते रहने की संभावना है । नियमों के अंतर्गत लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने के मामले में शुल्क को अगले पांच वर्ष के लिए रखना अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को दोबारा क्षति होगी । याचिकाकर्ता ने बताया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को मौजूदा शुल्कों और अन्य देशों से पाटन होने के कारण हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए देखने की आवश्यकता है ।
- झ) चीन के निर्यातक और उत्पादक भारतीय बाजार में अब भी विटामिन सी का पाटन कर रहे हैं । याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया है कि जिस कीमत पर चीन से सामग्री का आयात किया जा रहा है वह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में अत्यधिक कम है ।
- ञ) घरेलू उद्योग को अपने उचित मूल्य से कम मूल्य पर अपनी सामग्री बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा है क्योंकि घरेलू उद्योग कीमतों को बराबर करने के लिए

बाध्य था । इस प्रकार आयातों से घरेलू उद्योग उत्पाद को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हुआ । कंपनी अनेक स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने और उत्पादन की लागत में अत्याधिक कमी करने के बावजूद निरंतर वित्तीय घाटा उठा रहा है । विभिन्न स्रोतों से पाटित आयातों के कारण कंपनी को उत्पादन की लागत से भी कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

- ट) पाटन रोधी शुल्क लगाए बगैर आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है ।
- ठ) वर्षों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में अनेक स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद गिरावट आई है ।
- ड) आयातों का पहुंच मूल्य न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था परंतु घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम था । इस प्रकार आयातों के कारण भारतीय बाजारों में गंभीर रूप से कीमतें कम हो रही थी । मूल्य हास हो रहा था ।
- ढ) चीन से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है परंतु बहुत अधिक भी है । अत्याधिक पाटन मार्जिनों से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।
- ण) संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति पर बहुत ही अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।
- त) घरेलू उद्योग क्षमताओं की वृद्धि के बावजूद पर्याप्त मात्रा में रोजगार की वृद्धि नहीं कर सका है । इसका कारण घरेलू उद्योग द्वारा निरंतर घाटा उठाना है ।

थ) भारत में विटामिन सी की मांग में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है ।

10.3 प्राधिकारी की जांच

1. क्षति की पुनरावृत्ति अथवा जारी रहने के संबंध में धारा 9क(5) में इस प्रकार कहा गया है: -

"(5) इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटन रोधी शुल्क जब तक किसी प्रकार रद्द न किया जाए, इसके लागू होने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा;

परंतु यदि केंद्र सरकार की किसी समीक्षा में यह राय है कि ऐसे शुल्क को हटाए जाने से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय-समय पर अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए ऐसे अधिरोपण की अवधि को बढ़ा सकती है और ऐसी अगली अवधि इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के आदेश की तारीख से शुरू होगी । परंतु यह भी कि जहां 5 वर्ष की उक्त अवधि के समापन से पहले शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसे समापन से पहले समाप्त न हुई हो तो पाटन रोधी शुल्क ऐसी समीक्षा का निष्कर्ष निकलने तक आगे की अवधि के लिए लागू रह सकती है जो एक वर्ष से अधिक न हो ।"

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान से होने वाले आयातों की मात्रा न्यूनतम है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि जापान से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति दोबारा नहीं होगी अथवा जारी नहीं रहेगी ।

2. संबद्ध देशों से आयातों पर निरपेक्ष रूप से पर्याप्त वृद्धि: -

संबद्ध देशों से विटामिन सी के आयात निरपेक्ष रूप से बहुत अधिक हुए हैं ।

भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(ii) में निम्न प्रकार से व्यवस्था है: -

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो निरपेक्ष रूप से अत्याधिक वृद्धि हुई है"

वर्तमान मामले में चीन से विटामिन सी के आयात निरपेक्ष रूप से अत्याधिक हैं जो निम्नलिखित तालिका से देखे जा सकते हैं: -

विवरण	इकाई	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
आयात	मीट्रीक टन				
आयात चीन	मीट्रीक टन	405.54	227.73	290.67	130.97
आयात जापान	मीट्रीक टन	312.70	239.70	49.50	1.70
आयात ईयू व रूस	मीट्रीक टन	267.20	631.60	43.54	16.84
से आयात	मीट्रीक टन	985.45	1099.03	383.70	149.51
वे देश जिन पर शुल्क लागू है *					
अमरीका	मीट्रीक टन	63.11	134.76	51.33	230.51
कनाडा	मीट्रीक टन	0.00	7.00	27.40	152.08

	टन				
अमरीका, कनाडा	मीट्रीक टन	63.11	141.76	78.72	382.58
उपर्युक्त के अलावा आयात	मीट्रीक टन	9.36	41.78	18.00	76.31
कुल आयात	मीट्रीक टन	1057.91	1282.57	480.43	608.41
* वे देश जिन पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लागू है ।					
कुल घरेलू उत्पादन	मीट्रीक टन	269.28	237.25	544.88	456.90
देश में मांग	मीट्रीक टन	1327.20	1519.82	1025.31	1064.71
आयात में बाजार का हिस्सा					
चीन		38.33	17.76	60.50	21.53
जापान		29.56	18.69	1030	0.28
अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	%	25.26	49.24	9.06	2.77
अमरीका	%	5.97	10.51	10.68	37.89
कनाडा	%	0	0.55	5.7	25
अन्य देशों से आयात	%	0.88	3.26	3.75	12.54
कुल	%	100	100	100	100
डी जी सी आई एंड एस के अनुसार आयात आंकड़े					

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि चीन से होने वाले आयातों की मात्रा में गिरावट आई है तथापि यह फिर भी काफी महत्वपूर्ण हैं । आयातों की मात्रा को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । इसके अलावा, वर्तमान मामले में अधिक संगत बात यह है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग की क्षति की पुनरावृत्ति हो जाएगी अथवा जारी रहेगी । इस प्रकार आयात मात्राओं में संपूर्ण वृद्धि क्षति जारी रहने अथवा

पुनरावृत्ति होने की जांच करने के लिए पूर्वशर्त नहीं है । पाटित कीमतों पर आयातों की पर्याप्त मात्रा की मौजूदगी इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है ।

3. निर्यात कीमतों में पर्याप्त गिरावट: -

अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आयातों की मात्रा आयातों का कीमत प्रभाव है । संबद्ध देश के निर्यातकों ने कीमतें महत्वपूर्ण रूप से कम की हैं, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है: -

रूपए प्रति किग्रा.	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
चीन जन. गण.	231.66	226.14	213.57	188.5

उपरोक्त से यह प्रकट है कि संबद्ध देश से औसत निर्यात कीमत में गिरावट आई है । उपर्युक्त कीमतों को वर्तमान मामले की इन परिस्थितियों के तहत देखा जाना चाहिए कि इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । निर्यातकों की पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है ।

घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में अनेक मापदण्ड निम्नानुसार दर्शाते हैं: -

4. घरेलू उद्योग का उत्पादन

घरेलू उद्योग का उत्पादन, जो वर्षों से 2000-01 तक बढ़ा है, उसमें जांच अवधि में गिरावट आई है । इसके अतिरिक्त वह कीमत, जिस पर इस उद्योग

को अपना उत्पाद बेचने को बाध्य होना पड़ा, लाभकारी कीमत नहीं है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है ।

5. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है फिर भी यह 2000-01 तक बढ़ रही थी । इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को उत्पाद लागत से काफी कम कीमत पर बिक्री करने को बाध्य होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप लगातार हानि हुई ।

6. बिक्री कीमत

बाजार में मौजूद कुछेक देशों से हुए पाटित आयातों के मद्देनजर उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें कम करने को बाध्य होना पड़ा । यद्यपि, बिक्री कीमत में 1999-00 की तुलना में 2000-01 में मामूली वृद्धि हुई है तथापि जांच अवधि में इसमें दोबारा गिरावट आई है ।

7. कीमत कटौती

प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को उत्पादन की लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतें घटाने को बाध्य किया है । आयातित माल का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से पर्याप्त रूप से कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती हो रही है । अधिकतम से कम कीमतों के बावजूद कीमत कटौती हुई है ।

8. लाभप्रदता

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें अपनी उत्पादन लागत से कम रखने को बाध्य होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लगातार वित्तीय हानि हुई है । घरेलू उद्योग का उत्पादन 1998-99 की तुलना में बढ़ा है । तथापि, अधिक उत्पादन ने घरेलू उद्योग को अपने लाभों में सुधार लाने में मदद नहीं की है और घरेलू उद्योग का हानि उठाना जारी रहा ।

9. कीमत में कमी/ह्रास

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित माल का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से काफी कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में कमी/ह्रास हुआ ।

10. रोजगार और मजदूरी

घरेलू उद्योग को कर्मचारियों की संख्या कम करने को बाध्य होना पड़ा । इसके अलावा, कर्मचारियों की संख्या में कटौती के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा दी गई मजदूरी में भी गिरावट आई है ।

11. वस्तु सूची

घरेलू उद्योग की वस्तु सूची में गिरावट आई है । तथापि, वस्तु सूची में गिरावट को स्वयं उत्पादन में गिरावट के साथ देखा जाना चाहिए ।

12. नकद प्रवाह

लाभप्रदता के अनुरूप घरेलू उद्योग बाजार में उत्पाद के लगातार पाटन के कारण इस उत्पाद की बिक्री से निरंतर नकद हानि (2000-01 को छोड़कर) उठा रहा है । इसके अलावा नकद हानियां, जो 2000-01 तक गिरावट दर्शा रही थीं और घरेलू उद्योग ने वर्ष 2000-01 में नकद लाभ कमाया, वे जांच अवधि में दोबारा नकद हानि में तब्दील हो गए ।

13. उत्पादकता

उत्पादन में परिवर्तन के अनुरूप घरेलू उद्योग की उत्पादकता में 2000-01 तक वृद्धि हुई । तथापि इसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में फिर से गिरावट आई ।

14. वृद्धि

उत्पादन और बिक्री के अनुरूप घरेलू उद्योग की वृद्धि वर्ष 2000-01 तक सकारात्मक थी (यद्यपि यह वर्ष 1999-2000 में नकारात्मक थी), जांच अवधि में यह नकारात्मक हो गई थी ।

15. नए निवेश करने की क्षमता

निष्पादन की स्थिति अत्याधिक खराब हो जाने के कारण घरेलू उद्योग के लिए नए निवेशों की योजना बनाना कठिन हो गया है ।

16. जहां तक घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने अथवा उसके जारी रहने का संबंध है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । इस मामले में निम्नलिखित मापदंडों से यह पता चलता है कि चीन से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

1. यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादन और बिक्री की मात्रा में बढोतरी होने के बाद गिरावट आई है तथापि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से बिक्री की मात्रा और इस प्रकार उत्पादन की मात्रा में आगे और गिरावट आने की संभावना है । इससे क्षमता उपयोग, उत्पादकता, विकास और वस्तु सूचियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

2. यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग को हुए वास्तविक लाभों में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज होती है तथापि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से लाभों में आगे और गिरावट आने की संभावना है । इससे निवेश पर आय और नकद प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

3. यद्यपि जांच अवधि के दौरान चीन से विटामिन सी के आयात की कीमत से घरेलू उद्योग की कीमतों पर पहले से ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथापि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से कीमतों पर आगे और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के स्तर में आगे और वृद्धि हो जाएगी ।

10.4 उपर्युक्त को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति दोनों के जारी रहने अथवा उनमें पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

10.5 निष्कर्ष

- (क) चीन से पाटन मार्जिन अधिक है और आयातों की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है ।
 - (ख) पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात भी चीन से आयात भारत में उत्पादन एवं निर्यात सापेक्ष एवं निरपेक्ष दोनों रूप से अत्याधिक स्तर पर रहे हैं ।
 - (ग) संबद्ध देशों से निर्यात कीमत में गिरावट आई है ।
 - (घ) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है । यह गिरावट इस तथ्य के बावजूद है कि घरेलू उद्योग उप-ईष्टतम कीमतों पर कर रहा था (और उसे वित्तीय घाटा हो रहा था) ।
 - (ङ) आयातों की कीमतों में काफी कटौती हो रही थी और घरेलू उद्योग को कीमतों में उचित वृद्धि करने से रोका ।
 - (च) घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत से अत्याधिक निम्न कीमतों पर बिक्री के लिए विवश किया गया है ।
- इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । इसके अलावा यह भी देखा जा सकता है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को वापस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी ।

ट. कारणात्मक संबंध

11.0 प्राधिकारी का मानना है कि चीन जनवादी गणराज्य संबद्ध देश जो भारत में विटामिन सी का प्रमुख निर्यातक है, से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को

वास्तविक क्षति हुई है । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि संबद्ध देश की आयात की कीमतों से घरेलू उत्पाद की कीमत में कमी आई है और घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की बिक्री अपने उत्पादन लागत और नुकसानरहित कीमत से कम कीमत पर करने के लिए बाध्य होना पड़ा । जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग वसूली नहीं कर पाया । अतः घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

11.1 अन्य देशों से आयातों की मात्रा एवं मूल्य या तो निर्धारित सीमा से अधिक हैं या कीमतें अत्याधिक हैं अथवा उन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है ।

11.2 इस उत्पाद की मांग अधिक है । यद्यपि वर्ष 1998-99 और जांच अवधि के दौरान मांग में गिरावट का रुख प्रदर्शित होता है तथापि यह मालूम हुआ है कि इसमें जांच अवधि और पिछले वर्ष के बीच वृद्धि हुई है । इसके अलावा, यद्यपि वर्ष 1998-99 और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियों में सकारात्मक रुख प्रदर्शित होता है तथापि कुल आयातों में पर्याप्त गिरावट आई है । याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि डीजीसीआई एंड एस द्वारा संकलित एवं जारी किए जा रहे आंकड़ों में पूर्ण सूचना नहीं दी जा रही है । जो भी हो, चूंकि वर्ष 1998-99 और जांच अवधि के बीच घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि प्रदर्शित होती है इसलिए मांग में कमी आने से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है । जहां तक पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आने का संबंध है, यह बात नोट की जाती है कि मांग में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है और यद्यपि घरेलू उद्योग को बिक्रियों का नुकसान हुआ है तथापि आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

11.3 खपत के रूप में परिवर्तन व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन जैसे कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है ।

11.4 निम्नलिखित कारक यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति पहुंची है: -

- (क) संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम थी जिसने अन्य स्रोतों, जिन्हें पहले पाटन करते हुए पाया गया था, पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात उचित कीमत की वसूली से घरेलू उद्योग को रोका ।
- (ख) संबद्ध देशों के आयातों में काफी वृद्धि हुई है । इसके प्रत्यक्ष फलस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्रियों में गिरावट आई है ।
- (ग) असंख्य स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ ही देश में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की मांग में वृद्धि हुई । तथापि, चीन और अन्य स्रोतों से निरंतर पाटन के कारण इसमें पुनः गिरावट आई ।
- (घ) असंख्या देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में चीन और असंख्य देशों से निरंतर हुए पाटन के कारण कोई सुधार नहीं हुआ है ।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

12.0 पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य यह है कि सामान्य तौर पर ऐसे पाटन को समाप्त किया जा सके जिससे याचिकाकर्ता कंपनियों को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में पुनः खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति लाई जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है ।

12.1 यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विटामिन सी के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप निर्यात बाजार में उनके उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किंतु पाटनरोधी उपायों

से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेषकर तब, जबकि लगाए जाने वाला पाटनरोधी शुल्क याचिकाकर्ता कंपनियों को हुए नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक राशि तक ही सीमित कर दिया जाए। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से डम्पिंग द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभों को समाप्त किया जा सकेगा, याचिकाकर्ता कंपनियों को रोका जा सकेगा और इस प्रकार विटामिन सी के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

- 12.2 घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने भारत में याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए विटामिन सी की नुकसानरहित बिक्री कीमत पर विश्वास किया है और इस संबंध में घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की ईष्टतम लागत और उचित लाभ पर विचार किया है।

ड. पहुंच मूल्य

- 13.0 आयातों के पहुंच मूल्य का निर्धारण पाटन से संबंधित पैरा में ऊपर यथा उल्लिखित विटामिन सी की निर्यात कीमत के आधार पर सीमाशुल्क के प्रचलित स्तर तथा एक प्रतिशत उतराई प्रभारों को जोड़ने के बाद किया गया है।

ढ. निष्कर्ष

- 14.0 प्राधिकारी ने पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि

(क) चीन मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी (एस्करोबिक एसिड) का निर्यात भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके

फलस्वरूप पाटन हुआ है । लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से बाजार में विटामिन सी का निरंतर पाटन होता रहेगा ।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होगी ।

(ग) पाटित आयातों से संचयी क्षति हुई है । चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी के सभी आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक समझा जाता है ।

15.0 प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के बराबर या इससे कम के पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी । जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । इस प्रयोजनार्थ आयातों की औसत पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित बिक्री कीमत के साथ की गई थी । जहां कहीं भी अंतर पाटन मार्जिन से कम था, पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी । चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी के सभी आयातों पर अंतिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझा जाता है ।

16.0 तदनुसार, प्राधिकारी ने इसलिए चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क शीर्ष 2936.27 के अंतर्गत आने वाले "मर्क इंडेक्स" (जिसे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के एंट्री संख्या 867 के अंतर्गत यथा उल्लिखित विटामिन सी तथा विटामिन सी के अधिकतर प्रयोग में लाए जाने वाले समान पदार्थों जैसे एसकोर्बिक एसिड, एल-जाइलो स्कोर्बिक एसिड, 3-ओक्से-एल-गुलोफरानोलेक्टोन (एनोल रूप में), एल-3-केटोथ्रेओटेक्सुरोनिक एसिड लैक्टोन आदि के सभी आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लिया है । पाटनरोधी शुल्क निम्नांकित तालिका के कॉलम (9) में उल्लिखित राशि तथा प्रति किलोग्राम आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा जिसे संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर लगाया जाए ।

17.0

क्र सं	उपशीर्ष	उत्पाद का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2936.27	विटामिनसी तथा इसकी व्युत्पत्तियां	कोई भी विनिर्देशन	चीन जन. गण.	कोई अन्य देश	कोई उत्पादक	कोई अन्य निर्यातक	10.11	किया.	अमरीकी डॉलर
2	2936.27	विटामिनसी तथा इसकी व्युत्पत्तियां	कोई भी विनिर्देशन	कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई उत्पादक	कोई अन्य निर्यातक	10.11	किया.	अमरीकी डॉलर

18.0 इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9ख के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

19.0 इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2003

Subject : —Anti-dumping Investigation (Sunset Review) concerning imports of Vitamin-C from China and Japan—Final Findings.

No. 14/14/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

A. PROCEDURE:

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-
 - i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) notified final findings vide Gazette Notification No. 11/1/97-ADD dated 25.05.1998 recommending imposition of anti-dumping duties on all imports of Vitamin C originating in or exported from China PR and Japan. The duties were imposed vide customs notification No. 53/987 dated 24.07.1998.

- ii) The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made thereunder require the Authority to review from time to time the need for the continued imposition of definitive anti-dumping duty imposed by the Central Government. Consequent upon a petition filed by one of the Indian Producers, the Authority issued Public Notice vide Notification No. 11/1/99 dated 9.7.1999 for initiation of mid-term review for the continuance of Anti Dumping Duty imposed on Vitamin-C originating in or exported from China PR and Japan and considered appropriate to continue the imposition of Anti Dumping Duty, which was notified vide final findings Notification dated 13.6.2000.
- iii) The domestic industry M/s. Sarabhai M. Chemicals has now submitted an application for continuance of Anti dumping Duty on Vitamin C originating in or exported from China PR and Japan for a further period of 5 years.
- iv) Having decided to review the existing Anti Dumping Duty in force, the Authority issued a public notice dated 14th August 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Sunset Review of anti-dumping duty concerning the subject goods originating in or exported from subject countries classified under heading 2936.27 of the Custom Tariff Act.
- v) The Authority forwarded a copy of the initiation notification, non confidential petition filed by the domestic industry and questionnaire proforma to following known exporters to furnish relevant information and their views on proposed continuance of Anti Dumping Duty:
- i. M/s. Takeda Chemical Ind.Ltd., Japan (M/s. BASF)
 - ii. M/s. National Chemicals & Pharmaceutical Corpn., China
 - iii. M/s. Hebei Whelcom, China

- vi) The Authority forwarded a copy of the initiation notification, non confidential petition filed by the domestic industry and questionnaire proforma to known importers and users of subject countries in India, to furnish relevant information and their views on proposed continuance of Anti Dumping Duty:

- 1 M/s. Softesule Pvt.Ltd., Mumbai
- 2 M/s. Pharmapak Pvt.Ltd., Mumbai
- 3 M/s. ESPI Ind. & Chem.P.Ltd. Hyderabad
- 4 M/s. Omni Protech Drugs Ltd. Pune
- 5 M/s. E.Merck India Ltd. Raigarh
- 6 M/s.Wyeth Laderle Ltd. Gujarat
- 7 M/s. Saicure Pharma P.Ltd. Ahmedabad
- 8 Anglo French Drugs & Ind.Ltd.,Bangalore
- 9 M/s.Vital Therapeutics Pvt.Ltd.,Secunderabad
- 10 M/s.Avit Chemicals P.Ltd., Aurangabad
- 11 M/s.Amstrin Pharma P.Ltd. Mumbai
- 12 M/s. Swift Chem Ltd. Mumbai
- 13 M/s. Stride Pharma Ltd., Mumbai
- 14 M/s. Sai Mirra Innopharma, Chennai
- 15 M/s. Sain Medicaments P.Ltd. Hyderabad
- 16 M/s. Gandhi Pharma, Chennai
- 17 M/s. Glaxo Smithline Pharma, Mumbai
- 18 M/s. Heinz India Ltd. Aligarh
- 19 M/s. Meyer Organics Ltd. Thane
- 20 M/s. Torrent Pharma Lrd. Mehsana
- 21 M/s.Sumae Pharma Pvt.Ltd., Bhimavaram
- 22 M/s. Teekay Menthol P.Ltd. Mumbai
- 23 M/s. Safex Int., Ahmedabad
- 24 M/s.Venky's India Ltd.
- 25 M/s. Kare Labs Pvt.Ltd., Goa
- 26 M/s. Remedex Pharma Pvt.Ltd., Bangalore
- 27 M/s.Liva Pharma Ltd. Nasik
- 28 M/s. Micro Nova Pharma, Bangalore
- 29 M/s. Bajaj Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai
- 30 M/s.Chem Innova Remedies, Hyderabad
- 31 M/s. Emil Pharma Ind., Thane
- 32 M/s.Dr. Reddy's Lab, AP
- 33 M/s.Pfizer Ltd. Mumbai
- 34 M/s.CFL Pharma Ltd., Goa
- 35 M/s.Beassica Pharma & Chem, Mumbai
- 36 M/s. Bezel Pharmacap. Bulsar
- 37 M/s. BASF India Ltd. Navi, Mumbai

- vii) The Authority forwarded copy of the initiation notification, non confidential petition filed by the domestic industry and questionnaire proforma to Embassy of subject countries in India, requesting them to advise the producers and exporters in their country to respond to the initiation notification in the prescribed proforma within the time limits prescribed.

- viii) None of the producers/exporters from subject countries responded with relevant information to the Designated Authority.
- ix) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 15th January 2003. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any.
- x) Arguments raised by the interested parties in the form of written submission have been considered in the Final Findings.
- xi) In accordance with Rule 16 of the Rule supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have been duly considered in these Findings.
- xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties.
- xiii) The Authority also conducted cost investigation and worked out optimum cost of production/ cost to make and sell Vitamin-C in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles.
- xiv) The investigation covered the period 1st April 2001 to 31st March, 2002 (12 Months).

- xv) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the authority under the rules.

B. PETITIONER'S VIEW:

2. The Petitioners have made following major submissions:

2.1 The product involved in the present investigation is Vitamin-C in all its form and derivatives. It is also known as ascorbic acid. It is classified under customs sub-heading no. 2936.27 under the Customs Tariff Act. It is also known by various synonyms such as L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number "867 of MERCK INDEX".

2.2 The exporters from China continue to dump the material in India. In fact, the exporters from China further reduced the prices in respect of their exports to India. Thus, dumping intensified from China.

2.3 The price at which the material was being exported was not only dumped price but also caused material injury to the domestic industry. The imports from China continued to cause material injury to the domestic industry. Further, revocation of Anti Dumping Duty in force would result in continuance and recurrence of material injury to the domestic industry.

2.4 Other arguments advanced by the domestic industry have been dealt at respective places in these findings.

2.5 The petitioner has made following major submissions on the views expressed by BASF:

- a) BASF India or BASF Germany has not filed any questionnaire response. Thus, the present participation by BASF is without providing relevant information. Petitioner requests the Designated Authority to kindly declare BASF as non-cooperating party.

- c) The exporter has not brought out any grounds justifying withdrawal of duty. Mere argument that price of the product have shot up in the post investigation period does not call for termination of the investigation or withdrawal of duty. The data or information of post period of investigation has no relevance in an Anti Dumping investigation. Petitioner understands that this is the practice of Designated Authority. In any case no parameter can be seen in isolation. It is not even denied by BASF that normal value has not increased in the post investigation period.
- d) Petitioner was earlier producing Vitamin-C from basic stage. However, continued dumping from a number of sources forced the domestic industry to switch over to intermediate, i.e. production from 2KGA (which is cheaper). Since the company is competent to produce from basic stage, non availability of 2KGA would not be a bottleneck with the petitioner. The whole argument of BASF is without merit and irrelevant.
- d) It is not understood how rising import prices of Vitamin-C would benefit those formulators who are under DPCO in case the anti dumping duty is continued. The product is not having ad-valorem or fixed amount of anti dumping duty. The product is having a variable form of duty and the same would decline in case the export price goes up.
- e) It would be seen that there is no merit in the arguments advanced by BASF. BASF has not disputed that dumping of the product continues and the injury to the domestic industry continues. Nor has BASF argued that revocation of anti dumping duty would not result in recurrence of dumping and injury. Such being the case there are sufficient grounds to confirm continuation of anti dumping duty on imports of Vitamin-C from Japan and China.

C. Views of Exporters, Importers and Other Interested Parties:**Exporters****3.1 Submission made by BASF AG**

- a) BASF AG has stated that it was not provided non-confidential version of the review petition filed by the domestic industry. The local producer Sarabhai Chemicals has filed this review petition with a request to the Authority to consider extending the current Anti Dumping Duties.
- b) BASF AG has stated that it has not exported any Vitamin-C of Japanese Origin to India during the period of investigation.
- c) BASF is of the opinion that the local producer has been given enough time and opportunity to improve their position for the past 5 years and in case after this period they have still been unable to make progress, logically there is no justification for a further extension.

Importers**2 Submissions made by M/s. Bajaj Health Care Pvt. Ltd. Mumbai**

In response to the initiation, they requested for a copy of non-confidential version of the petition for making their submissions. As requested, a copy of non-confidential version was forwarded to the company vide our letter no.14/14/2002-DGAD dated 6.1.2003. In response to disclosure, they have given their submissions highlighting various issues which have been dealt at relevant paragraphs in these findings. Some of the major issues raised by the Company are:-

- i. Complete information are not made available in the non-confidential version of the petition of the domestic industry.

- ii. Procedure followed by the Designated Authority are contrary to the provisions law. As per notice on Initiation dated 14.8.2002 does not contain adequate information as per rule 6(1).
- iii. The scope of investigation to be restricted only to Vitamin 'C' of specification BP/USP imported into India from subject countries.
- iv. Petitioner has no standing to file the petition on behalf of the domestic industry.
- v. The petitioner has marked the information relating to normal value and export price as confidential.
- vi. Petitioner has not submitted the required information as per application proforma IVA & IVB prescribed by the Authority.
- vii. Under the provision of rules 12(1), the Authority is duty bound to record a preliminary finding regarding dumping injury and causal link in the above anti dumping investigation.
- viii. The petitioner claims that the cost of production i.e. substantial decreased, however, the Authority wrongly states that there is increase in cost of production of petitioners.
- ix. Authority in the contravention of the Rule, has arbitrarily determined, margin of dumping for all procedures of Vitamin 'C' in China and Japan (Rule 17(3))

3.3 M/s Liva Health Care Ltd, Mumbai

They have stated that their consumption of Vitamin C is negligible and they would not participate in the public hearing / investigation;

D. EXAMINATION AND FINDINGS BY AUTHORITY

- 4.0 The submission made by the importers, exporters, users, domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules supra.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 5.0 The product under consideration in the present investigation is Vitamin C and most commonly used synonyms of Vitamin C like Ascorbic Acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number" 867 of MERCK INDEX"(also referred as subject goods) originating in or exported from China and Japan. Vitamin C is classified under the Customs sub-heading no. 2936.27 in the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

- 5.1 It has been argued by Bajaj Healthcare that there is a difference in production process employed by the domestic industry and by the producers in the subject countries. The Authority notes that neither the producers in the subject countries responded to the Review investigation, nor claimed a difference in the production process nor M/s. Bajaj Healthcare has either submitted any documentary evidence on the alleged difference and quantified the same. Under the circumstances, the argument with regard to alleged difference in the manufacturing process is rejected.

5.2 With regard to the difference in the production process, the authority notes that no cogent reasons have been adduced to justify restricting the scope of product under consideration to pharma grade. It has not been established that this was the only form of Vitamin-C imported into India. Further, it has not been established that pharma grade Vitamin-C and other types are different products and can not be technically and commercially substitutable. The authority notes that the importers M/s. Bajaj Healthcare has not provided information as per importers' questionnaire. The authority, therefore, holds that the product under consideration includes all forms of Vitamin-C.

5.3 In view of the above, the Authority confirms that the product under consideration in the present investigation is Vitamin-C, originated and exported from China and Japan. Vitamin-C is classified under the Customs subheading no. 2936.27 under the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

F LIKE ARTICLES

6.0 Rule 2(d) of the Anti dumping Rules specifies that "Like Articles" means an Article, which is identical or alike in respects to the product under investigation or in the absence of such an Article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination

The Authority notes that the Vitamin-C produced and sold by domestic industry and those imported from the subject countries have similar characteristics and should be treated as like articles. Vitamin-C produced by the petitioner and imported from China are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. While the argument of an importer with regard to difference in the production process is unsubstantiated and unquantified, even if it is assumed that there is a

difference in the production process, Vitamin-C produced by the domestic industry and imported from China are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

- 7.0 The Authority finds that there is no other argument disputing that Vitamin C produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported material and is substitutable to Vitamin C imported from the subject countries both commercially and technically. Opposing interested parties have failed to establish that Vitamin C produced by the domestic industry is not a like article to the imported product. Vitamin-C produced by the domestic industry has been treated as Like Article to the product exported from China within the meaning of Rule 2(d).

G DOMESTIC INDUSTRY

- 8.1 The present investigations are sunset review investigations to examine whether cessation of Anti Dumping Duty in force would lead to recurrence or continuance of dumping and injury. Further, a petition was filed by M/s. Ambalal Sarabhai Enterprises Limited having its Registered Office at Wadi, Baroda-390007. There are a number of other producers of Vitamin C in India. M/s. Amoli Organics Limited, is also a producer of the product, who has supported the petition. Earlier, M/s. Jayant Vitamin Limited had created capacity for production of Vitamin-C. However, the company has suspended the production for a long time. The information furnished by National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) corroborates this fact.
- 8.2 Authority notes, M/s New S-hem Search Ltd, Vadodara & M/s Kerbs Bio Chemicals Ltd. Hyderabad have started production after the period of investigation; whereas, other units, M/s Cardinals Drugs Ltd, M/s Tonira Pharma etc are reported making the product for export purposes. While M/s Bajaj Health Care has disputed standing of Ambalal Sarabhai as domestic industry, the Company has not given

any quantified data either about any of these companies or their own status with regard to subject goods.

8.3 Ambalal Sarabhai has provided information relevant to determination of standing and scope of domestic industry. As regards standing requirement, it is reiterated that the present investigations are review investigations, initiated in accordance with Section 9A(5) and Rule 23 and, therefore, requirements under Rule 5 are not attracted.

8.4 It is clarified that Amoli Organics has supported the petition. Moreover, production of Ambalal Sarabhai alone constitute a major proportion of the Indian Production.

8.5 In view of the foregoing and after carefully going through the arguments advanced by various interested parties, the authority holds that Ambalal Sarabhai accounts for a major proportion of Indian Production and thus constitutes domestic industry under anti-dumping duty Rules.

9.0 NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN

9.1 Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) "the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rule made under sub section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular mark situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

- a. comparable representative price of the like article when exporter from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- b. the cost of production of the said article in the country of origin alongwith reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub section (6).

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export of there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country or origin"

9.2 Submissions made by M/s.BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germany:

Vide their fax dated 19th September, 2002 in response to the initiation of Sunset Review Investigation, they have stated that:

- (a) They are one of the major producers and suppliers of Vitamin 'C' globally and wished to respond to the investigation.
- (b) With effect from 4th January, 2001, M/s. BASF and Takeda, Japan have merged their water soluble vitamin business. Under terms of agreement, Takeda, Japan would continue to produce water-soluble vitamins including Vitamin 'C' at their manufacturing location in Hikari, Japan.

- (c) M/s. Takeda, Japan does not market the products as this is the responsibility of BASF and its group companies.
- (d) BASF did not export any Vitamin 'C' of Japanese origin manufactured by Takeda, Japan to India during the period of investigation.
- (e) BASF did not export any Vitamin C of Chinese origin to India during the period of investigation.
- (f) As regards to exports to India in future they would request for a new shipper review.

9.3 Submissions made by the domestic industry :-

- (a) The Authority sent questionnaire to all the known exporters and producers of Vitamin-C in subject Countries. However, none of the exporters from subject countries responded to the Authority and furnished any information in the form and manner prescribed by the Authority. The Authority is, therefore, fully justified in proceeding with best available information, i.e., constructed normal value.
- (b) The petitioner has claimed export price based on the data published by the DGCI&S, Calcutta. Export price has been adjusted for commission, inland freight, overseas freight, packing & handling charges.

9.4 Authority's Position – Determination of normal value and export price

The Authority sent questionnaire to all the known exporters and producers of Vitamin-C in subject countries. However, none of the exporters from subject countries responded to the Authority in the form and manner prescribed by the Authority. The Authority has therefore no option but to proceed on the basis of best available

information available on record of the Designated Authority, in terms of Rule 6(8) of Anti Dumping Rules.

Petitioner claimed normal value based on estimates of cost of production. The Authority has carefully examined the information and evidence presented by the petitioner with regard to cost of production and have carried appropriate adjustments. The normal value has thus been determined on the basis of constructed cost of production.

The petitioner has claimed export price based on the data published by the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Kolkata. In the absence of any cooperation from any exporter from China, Designated Authority has determined export price on the basis of information as per DGCI&S.

The DGCI&S prices are CIF prices. For comparison at same level of trade, the Authority has adjusted the export price for commission, inland freight, overseas freight, packing, and handling charges on the basis of information furnished by the petitioner and best information available with the Authority.

The Authority notes that the volume and CIF price of imports from Japan are 1699 Kg. @Rs 800.17 per kg. The volumes are deminimus and no dumping margin has been determined.

9.5 DUMPING MARGIN

The Rules relating to determination of dumping margin provide comparison of normal value and export price provides as under: -

"6.(I) While arriving at margin of dumping, the designated authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level and in respect of sales made at a

nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

- 9.6 For the purpose of fair comparison between normal value and export price the Authority has considered the information furnished by the petitioner and the best information available. The comparison has been done at ex-factory level, as both the normal value and export price are at ex-factory level. The comparison shows the following dumping margins: -

Country	Normal value US\$/Kg	Export Price US\$/Kg	Dumping Margin US\$/Kg	DM as % of Export price
China	***	***	***	208.13
Japan	---	----	-----	De-minimus

The Authority holds that the volume of imports as also dumping margin from Japan is de-minimus.

INJURY:

- 10.0 Under Rule 11 supra, Annexure-II, When a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the

dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree;

10.1 Submission made by BASF AG

- a) There are at least three other Indian producers and they will also be affected due to the non-availability of the intermediate 2Keto Gulonic (2KGA) which all of them import from China. BASF understands that currently there are no offers or shipments from China for this intermediate and this situation will continue. The price of intermediate has increased and this situation will also continue. In case the current trend of prices continues, BASF fears that no 2KGA will be available from China, as Chinese producers would like to realise better value-addition for finished products.
- b) The sudden and drastic change in the price of intermediates would have already disturbed the profitability of formulations which are all under the Drug Price Control Order.
- c) The present world market prices, demand and supply position is completely different as compared to the period of investigation. Therefore, there is no likelihood of the recurrence of any injury and there is no justification for extension of the anti-dumping duty.

10.2 Submissions made by the domestic industry :- The domestic industry has provided all information relevant to injury determination desired by the Authority. Further, the domestic industry has made following major submissions:-

- a) BASF has not brought out any grounds justifying withdrawal of duty. Mere argument that price of the product have shot up in the post investigation period does not call for termination of the investigation or withdrawal of duty. The data or information of post period of investigation has no relevance in an Anti Dumping Investigation. Petitioner understands that this is the practice of Designated Authority. In any case no parameter can be seen in isolation. It is even denied by BASF that normal value has not increased in the post investigation period.
- b) It has been stated by BASF that the enough protection has been given to the domestic industry and, therefore, Anti-Dumping duty should be revoked. Petitioner submits that BASF is not the adjudicating authority.
- c) The duty can be revoked only if both dumping and injury have got eliminated. It is not even the case of BASF that dumping has ceased from the subject countries.
- d) In the instant case, the exporters have, in fact, reduced the prices and have absorbed anti dumping duty in force to some extent. Thus, in spite of imposition of anti dumping duty on imports from subject countries, dumping has continued and domestic industry continues to suffer injury.
- e) The Petitioner was earlier producing Vitamin-C from basic stage. However, continued dumping from a number of sources forced the domestic industry to switch over to intermediate. i.e. production of 2KGA (which is cheaper). Since the company is competent to produce from basic stage, non availability of 2KGA would not be a bottleneck with the petitioner. The whole argument of BASF on this issue is without merit and irrelevant.

- f) It is not understood how rising import prices of Vitamin-C would benefit those formulators who are under DPCO in case the anti dumping duty is continued. The product is not having ad-valorem or fixed amount of anti dumping duty. The product is having a variable form of duty and the same would decline in case the export price goes up.
- g) It would be seen that there is no merit in the arguments advanced by BASF. BASF has not disputed the argument of the domestic industry that dumping of the product continues and the injury to the domestic industry continues. Nor has BASF argued that revocation of anti dumping duty would not result in recurrence of dumping and injury. Such being the case there are sufficient grounds to confirm continuation of anti dumping duty on imports of Vitamin-C from subject countries.
- h) The Designated Authority is required to assess whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury. Under the Rules, the duty is required to be extended for a further period of five year in case removal of the anti dumping duty in force would result in recurrence of injury to the domestic industry. Petitioner states that injury to the domestic industry is required to be seen in the light of existing duties and injury due to dumping from other countries.
- i) The exporter and producer from China are still dumping Vitamin-C in the Indian market. Petitioner submits that the price at which material is being exported from China is significantly lower than the selling price of the domestic industry.
- j) The domestic industry has been forced to sell its material at below its fair value, since the domestic industry was forced the match the price. Thus, the imports forced the domestic industry to undersell the product. The company continues to suffer

financial losses in spite of imposition of anti dumping duty on a number of sources and significant reduction in cost of production. Dumped imports from various forced the company to lower the prices, even below the cost of production.

- k) The Landed price of import without prevailing anti dumping duties is significantly below the selling price of domestic industry.
- l) The selling price of domestic industry over the years has declined in the spite of existing anti dumping duties on a number of sources.
- m) The landed value of imports was not only below the selling price of the domestic industry but also below the cost of production of the domestic industry. Thus imports were causing severe price suppression/depression in the Indian market.
- n) The dumping margin from China is not only more than de-minimus, but also very significant. Significant dumping margins have very adversely effected the performance of the domestic industry.
- o) The dumping from subject countries is very adversely affecting the cash flow situation of the domestic industry.
- p) The domestic industry has not increased employment to a significant degree in spite of addition of capacities. This is due to continued losses being faced by the domestic industry.
- q) There is no significant change in demand of Vitamin-C in India.

10.3 Examination of the Authority

1. With regard to recurrence or continuance of injury, Section 9A (5) states as under:-

- (5) *The Anti dumping duty imposed under this section shall, unless revoked either, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition;*

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti Dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.

Authority notes that volume of imports from Japan are de-minimus. The Authority holds that revocation of Anti Dumping Duty on imports from Japan would not lead to recurrence or continuance of injury to the domestic industry.

2. **Substantial increase in import from the subject countries in absolute term:**

The imports of Vitamin-C from the subject countries is significant in absolute terms.

Annexure-II (ii) of the Indian Anti-dumping rules provides as under: -

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms..."

In the instant case, imports of Vitamin-C from China in absolute terms are significant, as may be seen from the table below:

Particulars	Unit	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
Imports					
Imports-China*	MT	405.54	227.73	290.67	130.97
Imports-Japan*	MT	312.70	239.70	49.50	1.70
Imports EU and Russia*	MT	267.20	631.60	43.54	16.84
Imports from -Countries attracting duty*	MT	985.45	1099.03	383.70	149.51
USA	MT	63.11	134.76	51.33	230.51
Canada	MT	0.00	7.00	27.40	152.08
USA, Canada	MT	63.11	141.76	78.72	382.58
Imports Other than above	MT	9.36	41.78	18.00	76.31
Total Imports	MT	1057.91	1282.57	480.43	608.41
<i>* Countries already attracting Anti Dumping Duty.</i>					
Total Domestic Production	MT	269.28	237.25	544.88	456.30
Demand in the Country	MT	1327.20	1519.82	1025.31	1064.71
Market share in Imports					
China *		38.33	17.76	60.50	21.53
Japan *		29.56	18.69	10.30	0.28
Other Countries attracting duty	%	25.26	49.24	9.06	2.77
USA	%	5.97	10.51	10.68	37.89
Canada	%	0	0.55	5.7	25
Imports from Other countries	%	0.88	3.26	3.75	12.54
Total	%	100	100	100	100

Import data As per DGCI&S

It may be seen from the above table that even though there is a decline in the import volumes from China, the same are still very significant. The volume of imports must be seen in the light of the fact that there is an Anti Dumping Duty in force on the product. Moreover, what is more relevant in the present case is whether cessation of Anti Dumping Duty in force would result in recurrence or continuance of injury to the domestic industry. Thus, absolute increase in import volumes is not a precondition for examination of continuance or recurrence of injury. Existence of significant volumes of imports at dumped prices is sufficient for the purpose.

3. **Significant decline in export price:**

More significant than the volume of imports is the price effect of imports. The exporters from the subject country have reduced the prices significantly, as may be seen from the following table:

Rs. Per KG	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
CHINA PR	231.66	226.14	213.57	188.50

It is evident from the above, average export price from subject country has declined. The above prices must be seen under the circumstances of the present case that there is an Anti Dumping Duty in force on the product. There appears to be a tendency on the part of the exporters to absorb the Anti Dumping Duty earlier imposed.

Various parameters relating to the performance of the domestic industry shows as under: -

4 **Production of the domestic industry:**

The production of the domestic industry which had increased over the years till 2000-01, declined in the period of investigation. Further, the price at which the industry has been forced to sell the product is not remunerative price and is, therefore, causing injury to the domestic industry.

5. **Sales volume of the domestic industry**

Authority notes that the sales volume of the domestic industry have declined in the investigation period as compared to previous year, even though the same were increasing till 2000-01. Further, the domestic industry has been forced to sell at prices significantly below cost of production, resulting in continuous losses.

6. **Selling price**

The industry has been forced to reduce its selling prices, in view of dumped imports from a number of countries present in the market. Even though selling price increased marginally in 2000-01 over 1999-00, the same declined again in the investigation period.

7. **Price undercutting**

The Authority notes that the dumped imports have forced the domestic industry to reduce its prices in spite of increase in the cost of production. The landed value of the imported material is significantly below the selling prices of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market. The price undercutting is in spite of sub-optimal prices.

8. **Profitability**

The Authority notes that the industry has been forced to keep its selling prices below its cost of production, resulting in continued financial losses to the domestic industry. The production of the domestic industry increased when compared to 1998-99. However, higher production did not help the domestic industry in improving its profits and the domestic industry continued to make losses.

9. **Price suppression/depression**

The Authority notes that the landed value of the imported material is significant below the cost of production of the domestic industry causing price suppression / depression in the Indian market.

10. **Employment and wages**

The domestic industry has been forced to reduce number of employees. Further, the wages paid by the domestic industry has also declined as a direct consequence of reduction in number of employees.

11. **Inventories**

Inventories with the domestic industry have declined. However, decline in inventories must be seen alongwith decline in the production itself.

12. **Cash Flow**

On the lines of profitability, the domestic industry is suffering continuous cash losses (except 2000-01) from sale of the product due to continued dumping of the product in the market. Further, cash losses which were showing decline till 2000-01 and the domestic industry made cash profit in 2000-01, again turned into cash losses in the investigation period.

13. **Productivity**

On the lines of changes in production, productivity of the domestic industry increased upto 2000-01. The same has, however, declined again in the investigation period as compared to previous year.

14. **Growth**

On the lines of production and sales, growth of the domestic industry was positive upto 2000-01 (even though the same was negative in 1999-2000), the same became negative in the investigation period.

15. **Ability to raise fresh Investment**

The domestic industry is finding it difficult to plan fresh investments given that the performance has materially deteriorated.

16 With regard to recurrence or continuance of injury to the domestic industry, as stated earlier, the Authority is required to examine whether cessation of Anti Dumping Duty in force is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry. In the instant case, following parameters shows that the cessation of anti dumping duty on imports from China is likely to lead to continuation or recurrence of injury.

1. While actual volume of production and sales the domestic industry have declined after showing an increase, cessation of anti dumping duty is likely to lead to further decline in sales and hence production volumes. This would adversely affect the utilization of capacity, productivity, growth and inventories also.
2. While the actual profits realized by the domestic industry over the past few years show adverse trend, cessation of anti

dumping duty is likely to lead to further deterioration in profits. This would adversely affect return on investments and cash flow also.

3. While the import price of Vitamin-C during POI from China are already having adverse impact on the prices of the domestic industry, cessation of anti dumping duty in force would lead to further adverse impact on the prices, as the level of price undercutting and underselling would further increase.

10.4 In view of the above, it is concluded that cessation of anti dumping duty in force against Chinese imports would likely to lead to continuation or recurrence of both dumping and injury.

10.5 **Conclusions:**

- a) The dumping margins from China is significant and volume of imports are more than de-minimis;
- b) Imports from China have remained at very significant levels even after imposition of Anti Dumping Duty, both in absolute terms as also relative to production and consumption in India.
- c) The export price from the subject countries has declined.
- d) Selling price of the domestic industry have declined. The decline in the prices is in spite of the fact that the domestic industry was selling at sub-optimal prices (and was facing financial losses).
- e) The imports were causing severe price undercutting and prevented the domestic industry from effecting legitimate price increases;
- f) The domestic industry has been forced to sell at prices significantly below cost of production.

It may thus be seen that the industry has suffered material injury. It is further seen that injury to the domestic industry would continue should the Anti Dumping Duty in force be revoked.

K CAUSAL LINK:

11.0 The Authority holds that the material injury to the domestic industry has been caused by imports from China PR (subject country) that are major exporters of Vitamin C to India. The Authority notes that import prices from the subject country have undercut the price of the domestic product forcing the domestic industry to sell below its cost of production and non-injurious price which resultantly, the domestic industry was unable to recover. The material injury to the domestic industry was therefore caused by the dumped imports from the subject country.

11.1 Volume and value of imports from other countries are either de-minimis or the prices are significantly higher or are already attracting anti-dumping duties.

11.2 Demand for the product is on the increase. While the demand between 1998-99 and the investigation period shows declining trend, it is found that the same has increased between the investigation period and the previous year. Further, between 1998-99 and the investigation period, while the sales of the domestic industry shows a positive trend, total imports have declined significantly. Petitioner has alleged that the imports are not fully being reported in the data being compiled and released by the DGCI&S. In any case, since the sales of the domestic industry shows increase between 1998-99 and the investigation period, decline in the demand has not caused injury to the domestic industry. As regard decline in sales volumes in the investigation period as compared to previous

year, it is noted that demand has rather increased and while the domestic industry has lost sales, the imports have increased significantly.

- 11.3 Factors such as changes in pattern of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance does not appear to be a cause of injury to the domestic industry.
- 11.4 The following factors establishes that injury to the domestic industry has been caused due to dumped imports: -
- a. Landed price of imports from the subject countries was significantly lower than the selling price of the domestic industry, preventing the domestic industry from realizing fair prices after imposition of anti dumping duty on other sources earlier found to be dumping.
 - b. Imports from the subject countries have increased significantly. As a direct consequence, sales of the domestic industry have declined.
 - c. Market share of domestic industry in demand in the Country increased with imposition of anti dumping duty on a number of sources. However, the same declined again with continued dumping from China and continued dumping from other sources.
 - d. In spite of imposition of anti dumping duty on a number of countries, the profitability of the domestic industry has not improved due to continued dumping experienced from China PR and continued dumping from a number of countries.

L Indian Industry's Interest and other issues:

- 12.0 The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner companies and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- 12.1 It is recognised that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the petitioner companies. On the country, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner company(ies) and help maintain availability of wider choice to the consumers of Vitamin-C. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country/ies in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 12.2 To ascertain the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to the petitioner companies, the Authority has relied upon non-Injurious selling price of Vitamin-C in India for the petitioner companies, by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilization for the petitioner companies.

M. LANDED VALUE :-

- 13.0 The landed value of imports is determined on the basis of export price of Vitamin C determined as detailed above in the para relating to dumping, after adding the prevailing level of customs duties and one per cent landing charges.

N. CONCLUSIONS:

14.0 The Authority, after considering the foregoing, concludes that

(a) Vitamin-C (Ascorbic Acid) originating in or exported from China has been exported to India below normal value, resulting in dumping. Cessation of Anti Dumping Duty in force would result in continuation of dumping of Vitamin-C in the Market;

(b) The Indian industry has suffered material injury. Cessation of Anti Dumping Duty in force would result in continuation of injury to the domestic industry;

(c) The injury has been caused cumulatively by the dumped imports.

It is considered necessary to continue definitive anti-dumping duty, on all imports of Vitamin-C originating in or exported from China PR.

15.0 The Authority considered recommending the amount of Anti-Dumping Duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to domestic industry. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the non-injurious selling price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. It is considered necessary to impose definitive antidumping duty, on all imports of Vitamin C originating in or exported from China PR.

16.0 Accordingly, the Authority has therefore, decided to recommend definitive Anti-dumping Duty to be imposed, on all imports of Vitamin-C and most commonly used synonyms of Vitamin C like Ascorbic Acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number " 867 of MERCK INDEX"(also referred as subject goods) falling under Custom Heading 293627 originating in or exported from China PR. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column (9) table below and the landed value of imports per kg to be imposed on all imports of subject goods falling under Chapter 29 of the Customs Tariff, originating in or exported from subject countries : -

17.0

Sl. No	Sub Heading	Description of goods	Specification	Country of Origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	293627	Vitamin C & its synonyms	Any Specification	China PR	Any Country	Any Producer	Any Exporter	10.11	Kilogram	US \$
2.	293627	Vitamin C & its synonyms	Any Specification	Any country except China PR	China PR	Any Producer	Any Exporter	10.11	Kilogram	US \$

- 18.0 Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B and 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
- 19.0 An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority